हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

01 फरवरी 2025, समय 1810

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया।
- नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी।
- 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की। विपक्ष ने बजट की आलोचना की।
- उद्योग जगत ने भी बजट की सराहना की और इसे हर वर्ग को राहत देने वाला बताया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्ण बजट पेश किया।

बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34 लाख 96 हजार करोड़ रुपए और कुल व्यय पचास लाख 65 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28 लाख 37 हजार करोड़ रुपए रहने और राजकोषीय घाटा कुल घरेलू उत्पाद का चार दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। श्रीमती सीतारामन ने लोगों को राहत पहुंचाने वाली कई घोषणाएं की।

नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है जबकि वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हजार रुपए की मानक कटौती के कारण 12 लाख, 75 हजार रुपये होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर एक लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्तमंत्री ने बजट में नई कर संरचना के अनुसार कर स्लैब में भी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है। 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख तक 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख तक 15 प्रतिशत और 16 से 20 लाख तक 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है। 20 से 24 लाख रुपए की आय वाले करदाता के लिए 25 प्रतिशत कर की नई स्लैब घोषित की गई है। 24 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने किसी भी आकलन वर्ष की संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसके अलावा किराए पर TDS यानी स्रोत पर कर कटौती की लिए वार्षिक सीमा 2 लाख, 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा है कि नए कर ढांचे से मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत धन प्रेषण पर TDS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। माल की बिक्री से जुड़े लेन देन पर TCS हटाने का प्रस्ताव किया गया है, केवल TDS लागू रहेगा।

वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। इसी तरह स्टार्टअप पर ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यम स्थापित करने वाले 5 लाख उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। उन्हें 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी।

वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करदाताओं को भी राहत दी है। औद्योगिक सामान के लिए सीमा शुल्क दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजट में सात शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव 2023-24 के बजट में हटाई गई दरों के अतिरिक्त हैं। अब केवल 8 शुल्क दरें रह जाएंगी। बजट में औषधि/दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाइयों की सूची में डालने का प्रस्ताव है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह बजट देश के विकास को नई गति देगा।

हरियाणा के विभिन्न मंत्रियों और सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की है। जबकि भूपेन्द्र सिंह हूडा और कुमारी सेलजा सहित कई विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की है और कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है।

उद्योग जगत ने बजट की सराहना की है। पंचकूला में Indian Printed Circuit Association के अध्यक्ष रजनीश गर्ग ने कहा बजट अच्छा है।

हिसार से चार्टर्ड अकाउंटेंट सतीश मक्कड़ ने भी बजट को सब को राहत देने वाला बताया।